

छत्तीसगढ़ मंत्रपरिषद के महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यों?

6 सतिंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रपरिषद की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पछिड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिये पृथक्-पृथक् वभिगों के गठन के नरिणय के साथ ही अन्य कई महत्त्वपूर्ण नरिणय लिये गए।

प्रमुख बदि

- मंत्रपरिषद की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पछिड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिये पृथक्-पृथक् वभिगों के गठन का ऐतहासिक नरिणय लया गया। इससे इन वर्गों के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का अधिक सुव्यवस्थित तरीके से क्रयान्वयन हो सकेगा।
- राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के ज़िलों तथा बलियासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेंडरा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ज़िला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नयुक्त व्यक्तियों का स्थानांतरण, प्रतनियुक्ति, संवलयिन, संलग्नीकरण ज़िले और संभाग के बाहर नहीं कया जाएगा।
- कसिनों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नयिम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन कया गया, जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गोपालन के लिये लघु और सीमांत कसिनों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बना ब्याज के मलगा।
- राज्य में कसिनों के हति में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध वभिगों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रयान्वति करने के लिये अन्य वभिगों की भाँति नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में कृषि भवन के नरिमाण का नरिणय लया गया। इसके लिये एक रुपए टोकन में भूमि आबंटित करने का नरिणय लया गया।
- राज्य में पंप स्टोरेज आधारित जल वदियुत परयोजनाओं की स्थापना हेतु नविश को प्रोत्साहन देने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य जल वदियुत परयोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन कया गया।
- लघु जल वदियुत परयोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये वभिगीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन कया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता की लघु जल वदियुत परयोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना, जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का नरिणय लया गया।
- जल संसाधन वभिग की सचिाई नहरों के सरवसि बैंक में पक्की सड़कों का नरिमाण जल संसाधन वभिग की मद से कराए जाने की बजाय अन्य नरिमाण वभिगों की मद से कराए जाने का नरिणय लया गया, ताकि सचिाई वभिग की राशिका उपयोग राज्य में सचिाई क्षमता को बढ़ाने में कया जा सके।
- आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर केंद्रित लघु फलिंम और स्वतंत्रता के 75 वर्ष और आगामी 25 वर्ष में नए भारत के नरिमाण संबंधी डाक्यूमेंटरी नरिमाण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्यांश राशिका पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये वभिग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दसिंबर 2024 (मशिन अवधि) तक बढ़ाए जाने का नरिणय लया गया।
- मशिन अमृत 0 योजना के क्रयान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टैयरगि कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैधांतिकि स्वीकृति प्रदान की गई। मशिन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय नकियों को सम्मलित कया गया है, जिसके तहत नगरीय नकियों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमकता से कराया जाना है।
- प्रधानमंत्री कसिन ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम) योजना के कंपोनेंट-सी के अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत कये जाने हेतु 810 मेगावाट (डी.सी.)/675 मेगावाट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने के वभिगीय प्रस्ताव का अनुमोदन कया गया।
- कृषि पंपों का सोलरईजेशन कये जाने से कृषकों को कृषि पंपों के संचालन हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रही बजिली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अतः सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि पंपों का संचालन सोलर ऊर्जा से होगा तथा सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर वर्तमान में मलि रही बजिली मलित रहीगी।

